



कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी।

देहरादून

बाबुओं के आगे झुके ‘हाकिम’

कर्मचारियों के विरोध के चलते डीएम ने वापस ली स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था

देहरादून (एसएनबी)। जिलाधिकारी के नये स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था को वापस लेने के बाद बाबुओं ने अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार समाप्त कर दिया है। इससे पूर्व सोमवार को जिलाधिकारी ने संघ के पदाधिकारियों को बातचीत के लिये बुलाया, लेकिन कर्मचारी स्टाफिंग पैटर्न को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। आखिर में देर शाम जिलाधिकारी ने बाबुओं को पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करने के निर्देश दिये और नये स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था को खत्म कर दिया। नये स्टाफिंग पैटर्न के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाबू 30 जुलाई से तीन दिवसीय कार्यबहिष्कार पर थे लेकिन इस दौरान बाबुओं

को प्रशासन स्तर से वार्ता का कोई बुलावा न आने पर संघ ने आंदोलन को तेज करते हुए अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार शुरू कर दिया। बाबुओं के कार्यबहिष्कार के चलते आम जनता को खासी परेशानी का सामना

■ देर शाम हुए फैसले के बाद कर्मचारियों को पुरानी व्यवस्था के मुताबिक काम देखने के निर्देश



प्रयास किया जा रहा था। इतना ही नहीं अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बाबुओं को नोटिस जारी कर नयी व्यवस्था के तहत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दे दिये थे। जिससे बाबुओं में आक्रोश बना हुआ था। बाबुओं के तीखे तैवरों को देखते हुए जिलाधिकारी चंद्रेश कुमार यादव ने सोमवार को संयुक्त कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे

बाबुओं को वार्ता के लिये बुलाया लेकिन बाबू नये स्टाफिंग पैटर्न को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे और बातचीत के लिये नहीं आये। ऐसे में देर शाम जिलाधिकारी ने नये स्टाफिंग पैटर्न की लागू व्यवस्था को वापस ले लिया और बाबुओं को पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही कार्य दिखने के निर्देश दिये। इसका पत्र संघ को मिलने के बाद उन्होंने कार्यबहिष्कार को समाप्त करने का निर्णय लिया।

संघ के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार ने कहा कि यह एकजुटता की जीत है। धरने पर बैठने वालों में जिला सचिव देवेन्द्र सुन्दिर्याल, आशीष जोशी, राजेन्द्र रावत, अजय गोयल, अनिल कुमार, रविन्द्र कुमार, सुरेन्द्र सिंह आदि थे।

रजिस्ट्री को ऑनलाइन करने पर उखड़े वकील

देहरादून (एसएनबी)। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होने वाले काम को दो शिफ्टों में करने और रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के विरोध में बार एसोसिएशन ने पांच अगस्त को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इस मसले पर बार एसोसिएशन मंगलवार को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करेगा। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अन्य

एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता रघुबीर सिंह कटैत ने कहा कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा दो शिफ्टें शुरू की गई हैं। यह करने के विरोध में बार एसोसिएशन ने पांच अगस्त को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इस मसले पर बार एसोसिएशन मंगलवार को सब रजिस्ट्रार कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करेगा।

- रजिस्ट्रार कार्यालय में दो शिफ्टों में काम करने पर नाराजगी
- आज करेंगे हड़ताल

उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री करने वाला वकील सुबह से रात तक काम करता रहे यह संभव नहीं। इसके अलावा यदि रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन की जानी है तो उसे पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाए। हकीकत यह है कि काफी कामजात मैनुअल ही जमा करने होंगे। इसके अलावा कई रिकार्ड ऑनलाइन नहीं मिल पाते। ऐसे में दूसरी शिफ्ट दो बजे से रात नौ बजे तक। रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय के इस निर्णय का बार एसोसिएशन ने विरोध किया है। बार

अमीनों की हड़ताल से करोड़ों के राजस्व का नुकसान

देहरादून (एसएनबी)। उत्तराखण्ड राजस्व संग्रह अमीन संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकार को पूरे प्रदेश में हर दिन करीब एक करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं संग्रह अमीन बिना शासनादेश के हड़ताल को वापस लेने के मुद्दे में नहीं हैं। जिसके चलते पूरे प्रदेश में वसूली का काम पूरी तरह से ठप है।

सोमवार को परेड ग्राउंड में उत्तराखण्ड राजस्व संग्रह अमीन संघ के बैनर तले संग्रह अमीन चार सूत्री मांगों को लेकर चौधे दिन भी धरने पर बैठे रहे।

उन्होंने शासन में बैठे राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय महामंत्री विरेन्द्र कुमार सक्सेना ने कहा कि अमीनों की हड़ताल से सरकार को हर दिन एक करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा यह सरकार का शुद्ध राजस्व है। देहरादून, हरिद्वार, रुद्राक्ष, हल्द्वानी व उधमसिंह नगर में हर दिन सबसे अधिक वसूली होती है लेकिन उसके बाद भी शासन में बैठे अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कर्मचारियों की मांगों पर शासन में बैठे कुछ अधिकारी अड़णा लगा रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अन्य वक्ताओं ने कहा संघ अब आरपार की

लड़ाई के लिये तैयार है। कर्मचारियों को हर बार आश्वासन देकर शांत करा दिया जाता है, लेकिन इस बार बिना शासनादेश के कर्मचारी शांत नहीं होंगे।

धरने पर बैठने वालों में गुरु प्रसाद बहुगुणा, सुरेश प्रसाद सेमवाल, जिला सचिव गिरिजा शंकर चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष हरीश



परेड ग्राउंड में धरना देते संग्रह अमीन।

परिवार संग अनशन करने का ऐलान

देहरादून (एसएनबी)। ओएनजीसी हॉस्पिटल के गेट पर पैरामेडिकल संविदा कर्मचारियों का धरना सोमवार को चौथे दिन जारी रहा। नौकरी से बाहर किए गए पैरामेडिकल स्टाफ के 42 कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंदोलित हैं। नौकरी पर दोबारा बहाल न किए जाने पर संविदा कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि यदि ओएनजीसी प्रबंधन तत्काल प्रभाव में उनकी आठ सूत्री

- ओएनजीसी हॉस्पिटल के गेट पर पैरामेडिकल संविदा कर्मचारियों का धरना जारी
- ओएनजीसी प्रबंधन पर लगाया हठधर्मिता का आरोप, सरकार से लगाएंगे गुहार
- कहा, साजिश के तहत किया गया है नौकरी से बाहर, न्यायालय के आदेश की अवहेलना



ओएनजीसी अस्पताल के गेट पर धरना देते पैरामेडिकल कर्मचारी।

आउटसोर्सिंग कर्मियों का धरना पांचवें दिन भी जारी

देहरादून (एसएनबी)। आउटसोर्सिंग कार्मिक संघ रमसा ने सेवा विस्तार देने की मांग को लेकर सोमवार को धरना जारी रखा। संघ ने मांगों पर कार्रवाई न होने पर आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही आंदोलन रोज करने की चेतावनी दी है। सोमवार को पांचवें दिन शिक्षा निदेशालय में अध्यक्ष सुभाष लखेड़ा, उपाध्यक्ष वीपी सती, महासचिव आनन्द बड़ोनी, मीडिया प्रभारी योगेन्द्र बड़ोनी, शालिनी, रेखा ध्यानी व शबनम ने धरना दिया। मीडिया प्रभारी ने कहा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा

अभियान (रमसा) के अंतर्गत त्र सत्र में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रयोगशाला व कार्यालय सहायकों की नियुक्ति की गई थी। अनुबंध अवधि 31 मार्च को समाप्त होने के बावजूद सेवा विस्तार के लिए कार्रवाई नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि अनुबंध का नवीनीकरण न होने से कार्मिकों का भविष्य खतरा में है। सरकार को उनको सेवा विस्तार देने पर तत्काल विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मांग पूरी न होने पर पांच अगस्त को निदेशालय में झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

संविदा शिक्षकों का स्वास्थ्य और गिरा

देहरादून (एसएनबी)। पांच सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड पॉलीटेक्निक संविदा शिक्षक सोसायटी के सदस्यों का आमरण अनशन छठे दिन जारी रहा। आमरण अनशन पर बैठे संविदा शिक्षकों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। आमरण अनशन पर बैठे दो संविदा शिक्षकों की तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद भी वे आंदोलन पर डटे हैं।

- छठे दिन जारी रहा आमरण अनशन, दो संविदा शिक्षकों की तबीयत खराब
- सरकार के लिखित आश्वासन देने तक जारी रहेगा आंदोलन

द्वारा जिन 412 पदों को आयोग की परिधि से बाहर किया गया है उन पर कार्यरत संविदा शिक्षकों को समायोजित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि शीघ्र उनकी मांगों पर कार्रवाई न की गई तो वे आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से भी कोई आश्वासन दिए गए हैं। जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती आमरण अनशन जारी रहेगा। लगातार संघर्ष करने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। प्रदर्शनकारियों में सोसायटी अध्यक्ष सर्वेश चौधरी, दिशा नेगी, महेश कुमार, महेश भट्ट, अशोक कुमार, मुकेश सिंह, नरेश पाठक, श्वेता, सिमरन बडवाल, कविता भंडारी, मुनीर, नमिता तिवारी, पंकज डायर व नंदकिशोर सती आदि शामिल थे।



आमरण अनशन पर बैठे पॉलीटेक्निक संविदा शिक्षक।

सोलंकी अध्यक्ष और पुण्डीर मंत्री बने

देहरादून (एसएनबी)। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ (पूर्व माध्यमिक) की जिला कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न हो गया। सीधे मुकाबले में अनंत कुमार सोलंकी जयपद अध्यक्ष व रघुवीर सिंह पुण्डीर जिला मंत्री निर्वाचित किए गए। सोमवार को गांधी रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में सुबह आठ बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मतदान के दौरान प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ वोटों को रिक्राने में जुटे रहे। अपराह्न तीन बजे मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न हुई और सायं चार बजे से वोटों की गिती शुरू हुई। करीब 5.30 बजे चुनाव परिणाम घोषित किया गया। अध्यक्ष पद पर अनंत सोलंकी ने रविन्द्र सिंह पुण्डीर को करीब 71 मीतों से पराजित किया। अनंत सोलंकी को 335 व रविन्द्र सिंह पुण्डीर को 264 वोट मिले। मंत्री पद पर रघुवीर सिंह पुण्डीर ने 339 वोट हासिल

- जूनियर हाई शिक्षक संघ का चुनाव सम्पन्न
- विजयी पदाधिकारियों के समर्थकों ने जश्न मनाया

संभव प्रयास करने की बात कही। मीडिया प्रभारी सतीश धिलिडवाल ने बताया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों का चयन करेंगे। विदित हो कि दोनों पदों के चुनाव के लिए तीन अगस्त को नामांकन हुआ था।